हिन्दी दैनिक

# पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

वर्ष:4 अंक:329 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, बुधवार, 03 दिसंबर 2025


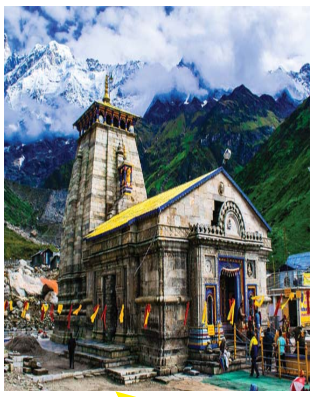

# सरदार पटेल आधुनिक भारत के शिल्पकार: पुष्कर सिंह धामी

**पथ प्रवाह, गांधीनगर/देहरादून**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को साधली, बड़ोदरा (गुजरात) में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सरदार@150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत आयोजित 'सरदार गाथा' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उत्तराखंड की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, विलक्षण संगठन क्षमता और राष्ट्रनिष्ठा से अखंड भारत का निर्माण किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरदार पटेल द्वारा खेड़ा तथा बारदोली के किसान आंदोलनों में अनीति के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने संवाद, दृढ़ता और निर्भीक निर्णयों के माध्यम से 562 रियासतों का भारत में विलय कर आधुनिक भारत की नींव रखी, जो इतिहास का अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना आज जन-जन तक पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि धारा 370 को समाप्त कर प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक देश, एक विधान' के संकल्प को पूर्ण किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि केवड़िया में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा–स्टैच्यू ऑफ यूनिटी–का निर्माण सरदार के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। देशभर में रन फॉर यूनिटी तथा विभिन्न प्रेरणादायी कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी है।

उन्होंने बताया कि सरदार@150 यूनिटी मार्च के तहत उत्तराखंड में सभी जिलों में एकता यात्राएँ आयोजित की गईं। स्वयं मुख्यमंत्री ने चार महत्वपूर्ण स्थानों पर इन यात्राओं में प्रतिभाग किया। इन यात्राओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति, योग, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सहकारिता मेलों के जरिए स्थानीय उत्पादों के संवर्धन से जोड़ा गया। कई ग्राम सभाओं में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर जनता की समस्याओं के समाधान भी सुनिश्चित किए गए। साथ ही विभिन्न गाँवों में सरदार उपवन विकसित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरदार पटेल के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की है, ताकि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानून सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सरदार@150 यूनिटी मार्च ने सरदार पटेल के एकता, समरसता और राष्ट्रगौरव के संदेश को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा– 'हमें सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।'

कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

## सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल लाई रंग, लक्सर स्टेशन पर दो ट्रेनों के ठहराव की मंजूरी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की लगातार पहल और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम आखिरकार सामने आ गया है। लक्सर रेलवे स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों–गाड़ी संख्या 14627/14628 सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस तथा 12357/12358 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस–का ठहराव केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। यह निर्णय क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह कदम जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लक्सर जंक्शन धार्मिक, औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां इन दोनों ट्रेनों का ठहराव होने से यात्रियों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इससे स्थानीय जनजीवन को राहत मिलेगी, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और जनता की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के लिए और भी सुविधाओं का विस्तार कराया जाएगा।

## मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 271.33 करोड़ की योजनाओं को दी स्वीकृति

### सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, पार्किंग, आंगनबाड़ी सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक निवेश

**पथ प्रवाह, देहरादून।**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों के लिए 271.33 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत परियोजनाओं में सड़क निर्माण, सिंचाई योजनाएं, मल्टीलेवल पार्किंग, आंगनबाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, जल निकासी व सीवरेज प्रणाली तथा पंचायतों की क्षमता वृद्धि से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। सबसे पहले जनपद नैनीताल के नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में रामनगर-भण्डारपानी-अमगढ़ी-बोहराकोट-तल्लीसेठी-बेतालघाट-रतोड़ा-भुजान-जैना-बिल्लेख मोटर मार्ग (शहीद बलवन्त सिंह मेहरा मोटर मार्ग) के किमी 58 से 69 के मध्य सड़क सुधारीकरण हेतु 10.28 करोड़ रुपये, तथा बेतालघाट विकासखंड के दूनीखाल-रातीघाट (पाडली) मोटर मार्ग पर 74.15 मीटर स्पान प्रीस्ट्रेस्ड पुल निर्माण हेतु 9.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट क्षेत्र में नागार्जुन-डहल-जालली मोटर मार्ग के सुधार के लिए 5.67 करोड़ रुपये, बागेश्वर जिले में कसियालेख-धारी मोटर मार्ग के उन्नयन हेतु 5.37 करोड़ रुपये, तथा चम्पावत जनपद के पाटी ब्लॉक अंतर्गत खेतीखान में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 6.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। साथ ही चमोली जनपद में नन्दा देवी राजजात यात्रा 2026 के लिए सेम-तोप पड़ाव में सामुदायिक हाल और पार्किंग निर्माण हेतु 3.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं के तहत लघु सिंचाई विभाग के कुल 33 कार्यों के लिए 61 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के लिए केन्द्रांश और राज्यांश मिलाकर 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

जनपद चमोली के जोशीमठ शहर की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखते हुए ड्रेनेज प्लान हेतु 40 करोड़ रुपये, तथा सीवरेज सिस्टम और एसटीपी निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए 54 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया।

इसके अलावा कोटद्वार क्षेत्र में खो नदी के बाएं तट पर स्थित ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा हेतु पहली किश्त के रूप में 3.21 करोड़ रुपये तथा नगर पालिका नैनीताल में वेंडिंग जोन निर्माण के लिए 4.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पंचायती राज विभाग के आरजीएसए कार्यक्रम के लिए नए लेखा शीर्ष खोलते हुए 58.42 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने श्रीमती मुन्नी देवी, निवासी पौड़ी, को उनके दिवंगत पति के स्थान पर 09 दिसंबर 2023 से प्रतिमाह 20 हजार रुपये पेंशन अनुमन्य किए जाने की मंजूरी भी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार एवं स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत पाँचवें, छठे और सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर्मचारियों एवं पेंशनरों के भत्ते में 2 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि लागू की गई है।

## भारत ने श्रीलंका के लिये मानवीय सहायता विमान उड़ान मंजूरी में देरी के पाकिस्तान के 'हास्यास्पद' दावे को किया खारिज

नयी दिल्ली। भारत ने श्रीलंका में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिये पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने में 60 घंटे से अधिक की देरी के पाकिस्तानी बयान को हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि यह मंजूरी उसी दिन पांच घंटे से भी कम समय में दे दी गयी थी।

भारत की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आयी है, जब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि श्रीलंका को मानवीय सहायता पहुंचाने के पाकिस्तान की कोशिशों में भारत बाधा बन गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार, राहत सामग्री लेकर श्रीलंका जा रहे एक विशेष सहायता विमान को भारत ने समय पर स्वीकृति नहीं दी, जिसकी वजह से विमान 60 घंटे की देरी से पहुंचा।

## सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं की वैधता पर उठाए सवाल

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रोहिंग्याओं की वैधता पर सवाल उठाते कहा कि क्या भारत सरकार ने कभी रोहिंग्याओं को 'रिफ्यूजी' घोषित करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय का यह सवाल उस याचिका के संदर्भ में सामने आया है जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने मई में पांच रोहिंग्या लोगों को हिरासत में गायब कर दिया था।

# सांसद खेल महोत्सव: डीपीएस में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

## रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत मंगलवार को विधानसभा रानीपुर ?क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, पिट्ठू, चम्मच दौड़ आदि खेलों प्रतियोगिताओं में 250 से अधिक बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और शिवालिकनगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री विमल कुमार, प्रधानाचार्य अनुपम जग्गा आदि ने प्रतिभाग कर रहे बालक बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में पहुंचे रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि खेलों का महत्व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासन, टीम वर्क और जीवन कौशल के विकास में है। खेल हमें स्वस्थ रखते हैं, तनाव कम करते हैं आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं। यह सहयोग, अनुशासन और हार-जीत को स्वीकार करने जैसे

महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सिखाते हैं। शारीरिक रूप से ये हृदय और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और फिटनेस बढ़ाते हैं। मानसिक रूप से, खेल तनाव कम करते हैं, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। सामाजिक रूप से, ये टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सिखाते हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमें 22 दिसम्बर से 24 दिसंबर तक होने वाली फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। ये फाइनल प्रतियोगिताएं स्टेडियम रोशनाबाद में संपन्न होगी। खेल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

ये रहे विशेष रूप से मौजूद: इस अवसर पर वाइस प्रिंसिपल परमिंदर सिंह, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, संजीव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, रितु ठाकुर, पंकज कुमार, मनोज सिंह, विक्रम भुल्लर, कैलाश भंडारी, बिंदर पाल, लज्जाराम, अंशुल शर्मा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे।

# डीएम की पत्नी प्रज्ञा दीक्षित ने सैनेटरी वेस्ट के पृथक्करण पर दिया जोर

## जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर महिलाओं में बढ़ाई जागरूकता

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नगर निगम रूड़की सभागार में मंगलवार को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण, उसके वर्गीकरण और आम जनता–विशेषकर महिलाओं–को इसके प्रति जागरूक करना रहा। कार्यशाला के तहत जादूगर वार्ड से इस योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई, जबकि बुधवार से स्कूलों में रेड वेस्ट के निस्तारण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डीएम की पत्नी एवं समाजसेवी प्रज्ञा दीक्षित रहीं। उन्होंने अपनी संस्था प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वच्छता व महिला जागरूकता अभियानों की जानकारी

साझा करते हुए कहा कि सैनेटरी वेस्ट का पृथक्करण स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पैड, डायपर और अन्य मेडिकल वेस्ट को निर्धारित रंग के डस्टबिन में डालना आवश्यक है, जिससे उनका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हो सके। प्रज्ञा दीक्षित ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निकाय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने चेताया कि गलत तरीके से फेंका गया मेडिकल वेस्ट संक्रमणों को बढ़ावा देकर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम खड़े कर सकता है।

नगर निगम रुड़की के नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि निगम शहर में बायोमेडिकल वेस्ट के लिए उन्नत प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा है। सहायक नगर आयुक्त अमरजीत कौर और शिवानी सालार ने अपशिष्ट वर्गीकरण की प्रक्रिया तथा निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी विक्रांत सिरोही ने मेडिकल वेस्ट के खतरों और उसके सुरक्षित निस्तारण की वैज्ञानिक तकनीकों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में नगर निगम की ब्रांड एंबेसडर रीना अग्रवाल ने प्रतिभागियों को स्वच्छता रैंकिंग में रुड़की को शीर्ष पर लाने का संकल्प दिलाया। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक मनसा नेगी ने निगम टीम के प्रयासों की जानकारी प्रस्तुत की। रोटरी क्लब से समीक्षा जैन, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने संबंधी सुझाव भी साझा किए।

# जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता को परखा, निर्देश जारी

**पथ प्रवाह, अल्मोड़ा**

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता परखने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा, निर्माणाधीन एएनएम सेंटर ढौरा तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढौरा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक स्थल पर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने लमगड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने नए सीएचसी भवन के निर्माण कार्य की प्रगति जानी और अधिशासी अभियंताओं को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की उपस्थिति, डिजिटल एक्स-रे मशीन की उपलब्धता, उसके संचालन हेतु टेक्निशियन की तैनाती, औषधि कक्ष, दवा स्टॉक, रोगी वार्ड, 108 सेवा, शौचालय व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत जांच की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ और आवश्यक

उपकरणों की उपलब्धता प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देश दिए कि बायोमेडिकल वेस्ट का सही पृथक्करण और निस्तारण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि संक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हो सके। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्यकर्मियों से संवाद कर अस्पताल की वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों की जानकारी ली तथा निर्देशित किया कि मानव संसाधन, उपकरण, दवाएं और सफाई से जुड़ी सभी आवश्यकताओं की सूची जिला प्रशासन को तत्काल प्रेषित की जाए। इसके बाद जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने ढौरा में निर्माणाधीन एएनएम सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और निर्माण की गति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केंद्र मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। निरीक्षण को गति प्रदान करते हुए जिलाधिकारी अंशुल सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढौरा पहुंचे। वहां उन्होंने विद्यार्थियों व शिक्षकों से संवाद किया। छात्रों की मांग पर जिलाधिकारी ने विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष और इंडोर गेम्स रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय के खेल मैदान के सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, एसडीएम संजय कुमार,

# गर्दन व चेहरे पर चोट के निशान, पुलिस संदिग्ध मौत की कर रही जांच

पथ प्रवाह, पथरी। हरिद्वार के गांव धारीवाला में मंगलवार को एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतक की गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, धारीवाला निवासी सुरेश पुत्र सुखबीर सिंह सुबह अपने कमरे में मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस पहुंचने से पहले ही परिवार के सदस्यों ने सुरेश को फंदे से नीचे उतार लिया था। प्रारंभिक जांच में न तो कोई सुसाइड नोट मिला और न ही परिस्थितियाँ साधारण आत्महत्या की ओर इशारा कर रही थीं। वहीं, मृतक के शरीर पर मौजूद चोटों ने पुलिस को हत्या की आशंका की ओर भी ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम तकनीकी साक्ष्यों, परिजनों के बयानों और घटनास्थल के हालात के आधार पर मामले

# स्वर्गीय धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे सन्नी और बॉबी देओल

पथ प्रवाह, हरिद्वार। फिल्म अभिनेता व पूर्व सांसद धर्मेंद्र की अस्थियां लेकर सन्नी देओल अपने भाई बॉबी देओल के साथ हरिद्वार पहुंच चुके है। अस्थि विसर्जन का यह कार्यक्रम बेहद गोपनीय रखा गया है। दोनों भाईयों ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है। हालांकि वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। स्थानीय मीडिया अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए टकटकी लगाए इंतजार करता रहा। लेकिन देर शाम तक दोनों भाई वीआईपी घाट पर नही पहुंचे। बीते दिनों फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई मे निधन हो गया था। स्वर्गीय धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट भी गोपनीय तरी?के से ले जाया गया और मीडिया से दूरी बनाकर रखी गई। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ इसी तरह बेहद गोपनीय तरीके से ही अस्थि विसर्जन करने की तैयारी है। मंगलवार को करीब डेढ़ बजे फिल्म अभिनेता सन्नी देओल के हरिद्वार पहुंचने के दो घंटे के बाद बॉबी देओल भी हरिद्वार पहुंच गए।

# सहकारिता से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार: मदन कौशिक

**पथ प्रवाह, हरिद्वार।**

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक हरिद्वार मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारिता से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह व सहकारिता के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। कृषि सहकारी समितियां अब बचत करने एवं ऋण देने तक सीमित नहीं है, डिजिटल हो गई है। ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेले का उद्घाटन करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि सहकारिता में अनेक लोग कार्य कर रहें है। जो लोकल उत्पाद तैयार कर रहें है उनकों बढ़वा देने के लिए यह सहकारिता मेला लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता से हजारों लोग जुड़े है। जो स्वयं सहायता के माध्यम से अपना रोजगार कर रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में लोकल उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को स्थानीय उत्पादकों से रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें।

### पांच लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण: आदेश चौहान

रानीपुर के विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सहकारी समितियों के विकास व किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 2021 में सहकारिता मंत्रालय शुरू हुआ। पशुपालन मछली पालन फूलों की खेती जैसी गतिविधियों के लिए सहकारी समितियां के माध्यम से पांच लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। एक लाख का व्यक्तिगत ऋण दिया जा रहा है। इससे महिलाओं का कौशल व परिश्रम बढ़ाने के साथ वह आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है।

### लखपति दीदी योजना से महिलाओं को लाभ: किरण

हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने कहा कि प्रदेश में 1.67 लाख लखपति दीदी बनी है। पीएम मोदी की भावना को सार्थक करते हुए सबसे पहले उत्तराखंड ने सहकारी समितियां को पूर्ण करने की दिशा में काम शुरू किया। प्रदेश की 5511 में से 3838 समिति का ब्यौरा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड हो चुका है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।

### सरकार कर रही मोटे अनाज को प्रोत्साहित: विकास तिवारी

भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी ने कहा कि मोटे अनाज को प्रोत्साहित करते हुए पिछले वर्ष 4270 रुपए रहा मड़वे का एमएसपी इस बार 4886 प्रति कुंतल किया है। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण पेंशन समिति अन्य योजनाओं को उल्लेख करते हुए उन्होंने आदर्श हरिद्वार के तहत किये जा रहे विकास कार्यों को गिनाया।

ये रहे मौजूद : उद्घाटन के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सुशील चौहान, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व निदेशक सुशील त्यागी, प्रमोद चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिला महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, चंदन चौहान, लव शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, आशु चौधरी, तरुण नैयर, प्रीति गुप्ता, राजू आ?दि उपस्थित रहे।

## एक नजर

### बीएचईएल स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर के नव-निर्मित प्रवेश द्वार का लोकार्पण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बीएचईएल उपनगरी के सेक्टर - 4 स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये नगर प्रशासन विभाग द्वारा बनाये गये नए प्रवेश द्वार का मंगलवार को विधिवत लोकार्पण किया गया। बीएचईएल हरिद्वार के महाप्रबंधक एवं प्रमुख रंजन कुमार ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए रंजन कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में निर्मित यह द्वार केवल एक संरचना मात्र नहीं है, बल्कि यह मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं संरक्षक मंदिर समिति संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि इस नए प्रवेश द्वार के माध्यम से, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन का एक और विकल्प प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस नए गेट के बनने से मंदिर परिसर सीधा मुख्य मार्ग से जुड़ गया है जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होगी। नगर प्रशासक एवं संपदा अधिकारी संजय पंवार ने कहा कि क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और सामुदायिक स्थलो के विकास के लिये भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी कार्यों को प्राथिमिकता दी जायेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, नगर प्रशासन विभाग के कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारी एवं क्षेत्रवासी आदि उपस्थित रहे।

### तीर्थ यात्रियों के साथ मारपीट के विरोध में सुभाष घाट पर व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने दिया धरना

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रोड़ी बेलवाला में यात्रीयों के साथ मारपीट के विरोध में प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल की शहर इकाई के तत्वाधान में स्थानीय व्यापारियों एवं तीर्थ पुरोहितों ने सुभाष घाट पर धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों द्वारा पोषित अतिक्रमणकारियों ने मेला मैदानों पर अतिक्रमण कर दुकानें लगा रखी हैं। जिनकी अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा। प्रवीण शर्मा ने कहा कि जिस क्षेत्र में यह मारपीट की घटना हुई है। उससे संबंधित पुलिस चौकी के स्टॉफ की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तभी अवैध अतिक्रमणकारियों पर लगाम कसी जा सकती है। तहसील अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि गुंडा तत्वों पर मुकदमा दर्ज होकर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। यदि प्रशासन इसमें हीलाहवाली करता है तो अगला प्रदर्शन कोतवाली पर आयोजित किया जाएगा। मारपीट की घटना का शिकार हुए तीर्थ यात्रियों के पुरोहित पंडित सुमित शर्मा ने विस्तार से घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा मारपीट के बाद तीर्थ यात्रियों के पक्ष में संबंधित चौकी को तहरीर देने पर संबंधित चौकी स्टाफ द्वारा भ्रमित किया गया। सुभाष घाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजू बधावा ने भी धरने को संबोधित किया और प्रशासन से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आदेश मारवाड़ी ने कहा कि तीर्थ यात्रियों का उत्पीड़न किसी सूरत में बर्दाशत नहीं होगा। धरना देने वालों में पंडित योगेश भारद्वाज, पंडित अश्वनी मोतीवाला, पंडित आदेश मारवाड़ी, पंडित नवीन वशिष्ठ, पंडित तरुण वशिष्ट, पंडित दीपक बागडोलिया पंडित मोनू सिखोला, अजय अरोड़ा, मनोज सिरोही, सुमित शर्मा, विमल सक्सेना, अनुज गुप्ता, निशा गुप्ता, अजय यादव, साजन साहनी, सोनू थपलियाल, महादेव आदि सहित सैकड़ों व्यापारी व तीर्थ पुरोहित शामिल रहे।

# एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर पुलिस ने की स्कूल के वाहनों की चैकिंग

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्कूली वाहनों की सघन चैकिंग की गई। इस दौरान सभी स्कूली वाहन चालकों से आवश्यक कागज़ात की जाँच कर सावधानी बरतने की हिदायत दी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा बच्चों की सुरक्षा हेतु स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग के दौरान पुलिस द्वारा ड्राइवरों से वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ जाँचने के साथ-साथ बच्चों को सुरक्षित ढंग से लाने-ले जाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की बात समझाई गई। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि बच्चों या अभिभावकों की ओर से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने नन्हे बच्चों को सड़क सुरक्षा, वाहन में बैठने के नियम और आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में सरल तरीके से जागरूक किया। पुलिस ने ड्राइवरों को वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट पहनने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की कड़ी हिदायत दी।

# ज्वालापुर में पुलिस का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, दी कड़ी चेतावनी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने मंगलवार को ज्वालापुर के बाजारों में अतिक्रमण हटाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने फिर से अतिक्रमण किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के अंतर्गत कटहरा बाजार, जामा मस्जिद, सर्राफा बाजार, घास मंडी, कस्साबान सहित आसपास के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को अतिक्रमण न करने एवं यातायात सुचारू रखने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान बाज़ार क्षेत्र में लगे अवैध रेहड़ी-ठेलों, तथा दुकानों के सामने किए गए अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाया गया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी गई कि यदि पुनः अतिक्रमण किया गया, तो उनके विरुद्ध कठोर चालान एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

# हरिद्वार में आठ रिटेल भंडारण सीज, ई-रवन्ना पोर्टल निलंबित

**पथ प्रवाह, हरिद्वार**

राजस्व को हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा खनन विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी रखने और अवैध गतिविधियों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के सख्त रुख को लागू करते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया। जिला खान अधिकारी मौ. काजिम खान ने बताया कि तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी क्षेत्र में अवैध खनन किए जाने की एक मौखिक दूरभाष शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए खनन विभाग और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार की संयुक्त टीम ने उनके नेतृत्व में मौके पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने रामपुर रायघटी एवं भिक्कमपुर जीतपुर स्थित 08 रिटेल भण्डारणों का भी surprise inspection किया। जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि इन सभी भंडारणों में गंगा नदी से अवैध रूप से रेत (उपखनिज) लाकर जमा की गई थी। अवैध खनन की पुष्टि होने पर प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सभी 08 रिटेल भंडारणों को मौके पर सीज कर दिया। इसके साथ ही इन भंडारण इकाइयों के ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, ताकि आगे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन या परिवहन पास जारी न किए जा सकें। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध खनन और राजस्व चोरी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खनन माफियाओं पर निरंतर सख्त निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

# संपादकीय

## उत्तराखंडः चमकते समारोह के पीछे दबती समस्याएँ

उत्तराखंड, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य और ऊँची पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, आज भी अपनी जनता के लिए कई मूलभूत सुविधाओं में दूरदर्शिता की कमी झेल रहा है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, राशन और कूड़ा प्रबंधन जैसी बुनियादी जरूरतें अब भी लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। जबकि राजधानी देहरादून में चमक-दमक और योजनाओं के उद्घाटन समारोहों की भरमार होती है, पहाड़ी जनपदों में जनता हर रोज़ अपने घरों और गांवों में सुविधाओं की कमी का सामना कर रही है।

जनता दरबार और स्थानीय शिकायत निस्तारण कार्यक्रमों में भी रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान धीमा और कभी-कभी बहाना बनकर रह जाता है। अतिक्रमण, अधूरी सड़कें, जर्जर पेयजल प्रणाली और असंगठित स्वास्थ्य सुविधाएँ साबित करती हैं कि सरकार के दावे और धरातल पर हालत में बड़ा अंतर है। पहाड़ों की जनता आज भी उसी सवाल के साथ जी रही है कि सूरज की पहली किरण के समान विकास की किरण उनके घर कब पहुंचेगी।

राजनीति का परिदृश्य भी यहाँ की वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आगामी 2027 के चुनावों की रणनीति में व्यस्त हैं। सरकारी नौकरियों, विकास परियोजनाओं और जनता कल्याण के मुद्दों को चुनावी हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। 26 हजार सरकारी नौकरी के दावे भले ही उपलब्धि की तरह पेश किए जा रहे हों, लेकिन पुलिस महकमे से लेकर तमाम विभागों में रिक्त पद वास्तविक समस्या को उजागर करते हैं।

असली सवाल यह है कि क्या ये घोषणाएँ केवल शोर मचाने का माध्यम बनकर रह जाएँगी या फिर पहाड़ी जनपदों में वास्तविक बदलाव लाएँगी। जनता दरबार में उठती आवाज़, अतिक्रमण और मूलभूत सुविधाओं की कमी, सरकार के खोखले दावों को सामने ला रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में विकास की असली चमक तभी दिखाई देगी जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर गांव और घर तक पहुंचे। जनता के लिए सशक्त स्वास्थ्य सेवाएँ, विश्वसनीय बिजली और पेयजल व्यवस्था, सुचारू सड़कें और कूड़ा प्रबंधन जैसी बुनियादी जरूरतें समय पर पूरी हों। सिर्फ चमकते उद्घाटन और रचनात्मक घोषणाओं से काम नहीं चलेगा; प्रशासनिक जवाबदेही, त्वरित कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी ही पहाड़ों में स्थायी विकास की किरण बन सकती है।

उत्तराखंड का वास्तविक गौरव तभी संभव है जब राजधानी की चमक के साथ-साथ पहाड़ों की समस्याओं का स्थायी समाधान भी दिखाई दे। जनता की आवाज़ को अनसुना करना अब विकल्प नहीं रह गया; इसे समय रहते सशक्त और ठोस कदमों में बदलना ही असली विकास होगा।

# सदन बनाम शोर, शीतकालीन सत्र की पहली भोर में राजनीतिक टकराव और संवाद की नयी चुनौती

कांतिलाल मांडोत

शीतकालीन सत्र हमेशा से राजनीतिक तापमान का आईना माना जाता रहा है। वर्ष के अंतिम महीने में जब केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तब विपक्ष इसे जवाबदेही और जनहित के मुद्दों को उठाने के अवसर के रूप में देखता है। इसी उम्मीद और उत्सुकता के बीच 1 दिसंबर से आरंभ हुआ संसद का यह शीतकालीन सत्र, अपने पहले ही दिन उस सौहार्द्र और गंभीरता से दूर दिखाई दिया जिसकी एक लोकतांत्रिक संस्था से अपेक्षा की जाती है।पहले दिन राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। कारण वही पुराना-हंगामा, नारेबाजी और तीखी राजनीतिक तल्खी। सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि संसद का मंच राजनीति की लड़ाई का एरिना नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर काम करने का स्थान है। उनकी टिप्पणी, सदन में ड्रामा नहीं, डिलेवरी चाहिए, में सिर्फ राजनीतिक व्यंग्य नहीं था, बल्कि कार्यसंस्कृति पर गंभीर चिंता का संकेत भी झलक रहा था।मोदी ने विपक्ष से यह भी कहा कि चुनाव परिणामों में पराजय मिलना राजनीतिक जीवन का अंग है, लेकिन पराजय की निराशा में डूबकर सदन को ठप कर देना लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार ट्रिप्स जैसी बहसों और विधायी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी संभव है जब विपक्ष मजबूत मुद्दे उठाए और सहयोग की भावना दिखाए।अचानक इस्तीफे पर राजनीति का बवंडर तेज हुआ।सत्र की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा राजनीतिक तूफ़ान उस वक्त खड़ा हो गया जब राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जैसे पदों को संभाल चुके धनखड़ के इस निर्णय ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे असामान्य कदम बताते हुए सवाल किया कि इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी छोड़ने के पीछे कौन-सा दबाव या परिस्थिति रही होगी। खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर खड़गे जी को इस विषय में बहुत तकलीफ हो रही है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह बयान दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच वाद-विवाद कैसे मोड़ ले सकता है।सत्र का एजेंडा बड़ा, लेकिन माहौल गर्म है।शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होना है। कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं और सरकार लगभग 10 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें तंबाकू और पान मसाला पर सेस लगाने वाला बिल, दिवाला कानून में सुधार, और जनविश्वास संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव शामिल हैं। संसदीय समितियों को भी कई रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इससे सरकार के विधायी कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडराते नजर आए। सरकार का आरोप है कि विपक्ष बिना पर्याप्त चर्चा के सिर्फ बाधा उत्पन्न करने की रणनीति अपना रहा है। वहीं विपक्ष कहता है कि उसके सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा और सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में हो रहे व्यवधानों पर स्पष्ट अपील की।मेरी चिंता यह है कि सदन चले। जनता हम सब से काम की उम्मीद करती है।

*नए सभापति का स्वागत और पुरानी राजनीति की छाया*

सत्र की शुरुआत में सी.पी. राधाकृष्णन को राज्यसभा के नए सभापति के रूप में स्वागत किया गया। मोदी ने उनके अनुभव की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही अधिक गरिमामय और प्रभावी होगी। लेकिन स्वागत समारोह के माहौल में भी दलगत राजनीति की तल्खी कम नहीं हुई।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के लिए अनुचित शब्द बोले। यह आरोप भी सत्र के शुरुआत में तनाव का एक और सूत्र बन गया।

विपक्ष के भीतर भी समानता नही लेकिन भिन्न आवाजेंसुनाई दी।हंगामे के इस माहौल में विपक्ष के भीतर भी अलग-अलग स्वर सुनाई दिए। गोगोई ने कहा कि अगर विपक्ष के मुद्दों को सत्र में उचित स्थान और चर्चा मिले, तो वे सरकार के सभी विधेयकों पर सहयोग करने को तैयार हैं। यह बयान संकेत देता है कि विपक्ष की मंशा केवल हंगामा करना नहीं है, बल्कि बहस और संवाद भी चाहता है।यदि उसे सम्मानजनक अवसर मिले।

हालाँकि, इस बीच राहुल गांधी सदन से उस समय बाहर निकल गए जब कार्यवाही हंगामे के कारण रुकावट का सामना कर रही थी। यह घटना भी राजनीतिक व्याख्याओं का विषय बनी।इस बीच चिराग पासवान ने कहा कि हंगामा छवि चमकाता है, काम नहीं,लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने विपक्ष के विरोध को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की।हंगामा करने वाला अपनी छवि चमकाता है, लेकिन काम नहीं करता। पासवान के इस वक्तव्य ने सत्ता पक्ष की उस भावना को मजबूत किया, जिसमें वे कहते हैं कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहा है और संसद के संचालन में बाधा डाल रहा है।

*हंगामा बनाम लोकतंत्र*

सत्र के पहले दिन जिस प्रकार कार्यवाही बाधित हुई, उसने इस विवाद को फिर जन्म दिया कि क्या लगातार हंगामे के माध्यम से विपक्ष अपनी भूमिका को कमजोर कर रहा है, या यह उनके लिए मजबूरी है क्योंकि सरकार उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं देती?सत्ता पक्ष का तर्क है कि हंगामा लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। संसद बहस, विचार और नीतिगत विमर्श का स्थान है, और लगातार व्यवधान से न सिर्फ विधायी कामकाज रुकता है, बल्कि जनता का विश्वास भी डगमगाता है।विपक्ष का दावा है कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकार की चुप्पीऔर अड़ियल रवैया उन्हें कठोर कदम उठाने पर मजबूर करता है।लोकतंत्र का बड़ा सवाल है किसदन में पहले दिन की उथल-पुथल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र किसी राजनीतिक परीक्षा से कम नहीं होगा। सरकार जहां विकास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर विधायी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष अधिक आक्रामक और तप्त सवालों के साथ तैयार बैठा है।

इस सत्र की असली कसौटी यह होगी कि क्या संसद अपने मूल दायित्व जनता के लिए कानून बनाना और शासन पर निगरानी रखना,को पूरा कर पाएगी या फिर राजनीतिक ध्रुवीकरण इसे फिर से जाम कर देगा?

लोकतंत्र का सार संवाद है, और संवाद के लिए बहस काअधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संयम का। पहले दिन की घटनाओं ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा राजनीतिक वर्ग इस संतुलन को पुनः स्थापित कर पाएगा। शीतकालीन सत्र की यह आरंभिक हलचल संकेत देती है कि आने वाले 18 दिन शांत नहीं रहने वाले। परंतु यदि सत्ता और विपक्ष अपने-अपने राजनीतिक हितों के ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें, तो यह सत्र महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दे सकता है।अंततः संसद जनता की उम्मीदों का मंच है। और इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए चाहिए न ड्रामा, न आरोपों का तूफान,बल्कि ठोस कार्य, सार्थक बहस और लोकतांत्रिक परिपक्वता। यह तभी सम्भव है,जब विपक्ष इस बात को समझे और समझकर उनकी जवाबदेही पर पुनः विचार करे।

# ताकि, संसद की कार्यवाही स्थगित न हो

दिलीप कुमार पाठक

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो देश की निगाहें संसद भवन की कार्यवाही पर टिकी होती है, क्योंकि देश को चलाने के लिए नियम -कानून तो यहीं बनते हैं, परंतु कुछ सालो से देखा गया है कि संसद भवन की कार्यशैली ही बदल गई है। सदन चलता कम स्थगित ज्यादा होता है, इसमे विपक्ष से ज्यादा सरकार ज़िम्मेदार है अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक दौर होता था जब संसद में खूब नोक-झोंक होती थीं, लेकिन आलोचनाओं के लिए स्थान होता था, तमाम असहमतियों के बावजूद विमर्श होता रहता था।

संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने जो कहा वो भाषा पीएम के लिहाज़ से उचित नहीं है। पीएम ने कहा - मेरी एक चिंता रही है, लंबे समय से सदन में जो पहली बार चुनकर आए हैं, या जो युवा हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है और न ही अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई भी दल हो हमें किसी को भी हमारी नई पीढ़ी के नौजवान सांसदों को, उन्हें अवसर देना चाहिए। यहां तक तो पीएम ने अच्छी बात कही लेकिन उसके बाद जो कहा वो बेहद रूखे शब्दों में की गई टिप्पणी है पीएम ने कहा - इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम के शब्द उदारवादी होने चाहिए, अगर विपक्षी पार्टियों ने कार्यवाही बाधित की है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन सीधे कहना कि ड्रामे के लिए जगह और हैं, मुझे लगता है कि पीएम के ऐसे शब्द संसद सत्र की गहमागहमी को और भी बढ़ा सकते हैं, वैसे भी विपक्ष सरकार पर हमलावार है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, भाजपा लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को खत्म करने पर तुली है। शीतकालीन सत्र सिर्फ 19 दिन का है, जिसमें से सिर्फ 15 दिन ही चर्चा हो पाएगी, यह शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा। इस सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है, उन्होंने कहा, हमने सुरक्षा की बात उठाई है कि इस शीतकालीन सत्र में सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो. इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा आता है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस पर संक्षिप्त चर्चा चाहती है लेकिन लोकतंत्र की रक्षा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, हमारी तीसरी मांग स्वास्थ्य की सुरक्षा की है। जिस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। चौथा विषय आर्थिक सुरक्षा है, जो किसान, श्रमिक है। उसे ना तो उचित मूल्य मिल रहा है, ना कारखाने में सुरक्षा मिल रही है लेकिन. ऐसे सारे अहम मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार बचना चाहती है।

ये गोगोई के तर्क हैं, परंतु संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। संसद में हर मुद्दे पर बहस होनी जरूरी है। कई मुद्दे सरकार के लिए उतने अहम नहीं होते जितने विपक्ष के लिए मायने रखते हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष की हठधर्मिता से टकराव उत्पन्न हो जाता है, जिससे संसद की कार्यवाही पर असर पड़ता है। संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक इसीलिए बुलाती है। शुरू में प्रश्नकाल होता है। इसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाए मुद्दों पर भागती है तो संसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है। अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है। कई बार विपक्ष जानबूझकर जनता पर प्रभाव दिखाने के लिए संसद की कार्यवाही को रोकने के लिए बाधा उत्पन्न करता है जो ठीक नहीं है। कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें देश का हित देखा जाता है अपना या पार्टी का नहीं ऐसे मुद्दों पर हंगामा करने से बचना चाहिए। संसद की कार्यवाही चलाने के लिए सभी दलों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करे और सरकार को चाहिए कि विपक्ष के उठाए मुद्दों को गंभीरता से लेकर उन पर चर्चा कराए। कई बार लगता है जिन मुद्दों पर विपक्ष संसद ठप करता है सरकार में आते ही उन मुद्दों को लागू करवाता है, जो सही बात नहीं है। देश सबसे पहले होना चाहिए। ख़ासकर सभी को बात कहने का समय मिलना चाहिए, पीएम की जिम्मेदारी अधिक होती है इसलिए पीएम को उदारवादी होना चाहिए जिससे सदन में मतभेद तो हों, लेकिन मनभेद न हों, जिससे संसद की कार्यवाही स्थगित न हो।

# 41 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है गैस त्रासदी का असर

योगेश कुमार गोयल

1984 में 2-3 दिसम्बर की रात भोपाल में मौत ने ऐसा तांडव मचाया था, जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। भयानक गैस त्रासदी की उस घटना को पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी और हृदयविदारक औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 2-3 दिसम्बर 1984 को आधी रात के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) से निकली जहरीली गैस 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' ने हजारों लोगों की जान ली थी। उस जानलेवा त्रासदी से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। दुर्घटना के चंद घंटों के भीतर ही कई हजार लोग मारे गए थे और मौतों का यह दिल दहलाने वाला सिलसिला उस रात से शुरू होकर कई वर्षों तक अनवरत चलता रहा। हालांकि इसी साल भोपाल के जहरीले कचरे का निपटान किया जा चुका है किन्तु भोपाल गैस कांड को 41 साल बीत जाने के बाद भी इसका असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इस त्रासदी से पीड़ित होने वालों के जख्म आज भी हरे हैं। भोपाल गैस त्रासदी पत्थर दिल इंसान को भी इस कदर विचलित कर देने वाली थी कि हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया था जबकि करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा था, आसपास के सभी पेड़ बंजर हो गए थे। एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से हजारों लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और जो जिंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी पल-पल मरने को विवश हैं। इनमें से बहुत से लोग कैंसर सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और घटना के 40 साल बाद भी इस गैस त्रासदी के दुष्प्रभाव खत्म नहीं हुए हैं। विषैली गैस के सम्पर्क में आने वाले लोगों के परिवारों में इतने वर्षों बाद भी शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे जन्म ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैस त्रासदी से 3787 की मौत हुई और गैस से करीब 558125 लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि कई एनजीओ का दावा रहा है कि मौत का यह आंकड़ा 10 से 15 हजार के बीच था तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक करीब 8 हजार लोगों की मौत तो दो सप्ताह के भीतर ही हो गई थी जबकि करीब 8 हजार अन्य लोग रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों के चलते मारे गए थे।

हजारों लोगों के लिए काल बने और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले भोपाल में यूसीआईएल के कारखाने का निर्माण वर्ष 1969 में हुआ था, जहां 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' (मिक) नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला गया लेकिन भोपाल गैस त्रासदी की घटना के समय तक उस कारखाने में सुरक्षा उपकरण ठीक हालात में नहीं थे और वहां सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। उस कारखाने के टैंक संख्या 610 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी और गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री था। पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा बिजली का बिल बचाने के लिए मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिया गया था। 3 दिसम्बर 1984 को इस कार्बाइड फैक्टरी से करीब 40 टन गैस का जो रिसाव हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ पानी मिल जाने से रासायनिक प्रक्रिया होने के परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड़ गया था और यह जहरीली गैस देखते ही देखते पूरे वायुमंडल में फैल गई।

# सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को पीजी की मान्यता, एमएससी नर्सिंग की 15 सीटें स्वीकृत

**स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में तेज हुआ कार्ययोजना पर अमल**

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने टिहरी जनपद के सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को बड़ी सौगात देते हुए उसे पीजी नर्सिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा क्रमांक 311/2025 के अंतर्गत मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें नर्सिंग कॉलेज को उन्नत रूप में विकसित करने से जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों से अब तक की प्रगति, अवसंरचना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों और निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पीजी नर्सिंग कॉलेज विकसित करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पहाड़ी जिलों में उच्च स्तरीय नर्सिंग शिक्षा और विशेषज्ञ नर्सिंग जनशक्ति तैयार करना राज्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऐसे में यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### पीजी मान्यता के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने बताया कि शासन स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां 14 अगस्त 2025 को जारी की जा चुकी थीं। इसके बाद 12 नवम्बर 2025 को एक निरीक्षण समिति गठित की गई, जिसे कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। शासन द्वारा अब सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज को आधिकारिक रूप से पीजी नर्सिंग कॉलेज का दर्जा प्रदान कर दिया गया है।

### निरीक्षण में अवसंरचना संतोषजनक पाई गई

गठित निरीक्षण समिति ने 14 नवम्बर 2025 को कॉलेज परिसर का व्यापक मूल्यांकन करते हुए पाया कि कॉलेज में भवन, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, मल्टीपरपज़ हॉल, अतिरिक्त कक्षाएँ और संपूर्ण शैक्षणिक संसाधन पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। समिति ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण हेतु जिला चिकित्सालय बौराड़ी (100 बेड) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरेंद्रनगर (50 बेड) जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो एमएससी नर्सिंग शिक्षा की अनिवार्य शर्तों को पूरा करती हैं। कॉलेज के पास कुल 71,900.33 वर्गफुट क्षेत्र है, जिसमें उचित शैक्षणिक एवं हॉस्टल संसाधन सम्मिलित हैं।

### एमएससी नर्सिंग की 15 सीटें स्वीकृत

समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज में एमएससी नर्सिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए 15 नई सीटों की संस्तुति की गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यह निर्णय पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और टिहरी जनपद में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री घोषणा की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में डॉ. एके आर्य, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, डॉ. रविन्द्र सिंह बिष्ट, अपर निदेशक, मनीषा ध्यानी, रजिस्ट्रार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

## एक नजर

### पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज बनेगा एक मॉडल मेडिकल इंस्टीट्यूट, नए साल पर कार्य पूर्ण

**पथ प्रवाह, देहरादून**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा का नया युग तेजी से आकार ले रहा है। इसी कड़ी में सीमांत पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में बन रहा राजकीय मेडिकल कॉलेज अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। भौगोलिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों के बावजूद जिस गति से इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य हुआ है, वह राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है। राजकीय मेडिकल कॉलेज का विशाल परिसर अब लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है। आधुनिक मानकों पर निर्मित फैकल्टी भवन, लैबोरेट्री, परीक्षा-लेक्चर थिएटर, हॉस्टल ब्लॉक, प्रशासनिक भवन और आवासीय परिसर– ये सभी संरचनाएँ पिथौरागढ़ को आने वाले समय में पहाड़ का प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनाने की ओर मजबूत संकेत देती हैं। स्थानीय जनमानस भी इस परियोजना को लेकर उत्साहित है। लोगों का मानना है कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहरी जिलों या राज्यों पर निर्भरता समाप्त होगी, वहीं रोजगार, व्यवसाय और सेवाओं के नए अवसर पिथौरागढ़ में तेजी से बढ़ेंगे।

सरकार ने 31 मार्च 2026 तक कॉलेज को पूर्ण रूप से तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और पेयजल निगम की ताज़ा प्रगति रिपोर्ट बताती है कि यह लक्ष्य समय पर हासिल होने की प्रबल संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश प्रमुख ब्लॉक 70% से 95% तक पूरे हो चुके हैं। फैकल्टी ब्लॉक, लैबोरेट्री और लेक्चर थिएटर 65-80% तक बन चुके हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 45% कार्य पूरा हो चुका है।

हॉस्टल भवनों में निर्माण कार्य सबसे अधिक गति से हुआ है। बॉयज़ हॉस्टल 90% और गर्ल्स हॉस्टल 80% तक पूर्ण हो चुके हैं। गर्ल्स डाइनिंग ब्लॉक 78% और बॉयज़ डाइनिंग 35% निर्माण स्थिति में है। आवासीय ब्लॉक–टाइप-6 और टाइप-4–85 से 96% तक तैयार हैं, जो भविष्य में कॉलेज संचालन को सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

अस्पताल परिसर में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इमरजेंसी ब्लॉक की रिमॉडलिंग 90% तथा IPD-1 में 75% कार्य पूरा हो चुका है। OPD-2, जूनियर रेजिडेंट हॉस्टल और इंटर्न हॉस्टल में कार्य विभिन्न चरणों में जारी है। IPD-2, IPD-3, नर्स हॉस्टल, BMW ब्लॉक और मोर्चरी जैसे ब्लॉक शुरुआती चरण में हैं, लेकिन विभाग का दावा है कि इन पर भी शीघ्र गति आएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा– 'हम सिर्फ इमारत नहीं, एक मॉडल मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं ' स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि, 'पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री धामी जी की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में शामिल है। सीमांत जिले को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। अधिकांश प्रमुख ब्लॉकों में उत्कृष्ट प्रगति हुई है और शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बनाना नहीं, बल्कि इसे राज्य का मॉडल मेडिकल इंस्टीट्यूट विकसित करना है। '

### फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-1234 को मंगलवार सुबह बम की धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों के मुताबिक, हैदराबाद एयरपोर्ट को एक ईमेल मिला था, जिसमें विमान में बम होने की बात लिखी थी। इसके बाद तुरंत सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एयरबस ए321-251 एनएक्स विमान रात 1:56 बजे कुवैत से उड़ा था और सुबह 8:10 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। विमान को सुरक्षित तरीके से उतारकर एयरपोर्ट के अलग-थलग इलाके में ले जाया गया है, जहां बम स्क्वायड और सुरक्षा टीमें पूरी जांच कर रही हैं। यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।

### हिमालय के शिकारी लगा रहे आग

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित बुग्यालों में इन दिनों शिकारी एक्टिव हो गए हैं, जंगली जानवरों के शिकार के लिए वह यहां पर आग लगा रहे हैं। आंशका जताई जा रही है कि ये सब शिकारियों ने किया है, जो दुर्लभ जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जिसके बाद अब पिथौरागढ़ का वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। डीएफओ ने इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सेना को लेटर लिखा है, जिसमें आईटीबीपी और एसएसबी की मदद मांगी है।

## हौसले की पाँच मिसालें: पौड़ी के पाँच दिव्यांगजन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित

**विश्व दिव्यांग दिवस पर उत्तराखंड सरकार करेगी सम्मानित**

पथ प्रवाह, पौड़ी।

विश्व दिव्यांग दिवस उन अदम्य इच्छाशक्तियों और संघर्षों को सलाम करने का अवसर है, जो सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि संभावनाओं के विस्तार में विश्वास रखते हैं। इस वर्ष पौड़ी जनपद के पाँच दिव्यांगजन अपनी उपलब्धियों, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित हुए हैं। ये पाँच नाम न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी हैं, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा के सशक्त प्रतीक भी हैं। आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, स्वयं-रोजगार से आजीविका अर्जित करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों, प्रतिभावान खिलाड़ियों तथा सेवा-योजकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करेगी। यह सम्मान उन दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने सीमाओं से ऊपर उठकर समाज को नई दिशा और दृष्टि दी है।

अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल ने जानकारी दी कि इस वर्ष पौड़ी से पाँच व्यक्तियों का चयन हुआ है, जिनमें दो दक्ष दिव्यांग कर्मचारी और तीन स्वयं-रोजगार में सफल दिव्यांगजन शामिल हैं। दक्ष दिव्यांग कर्मचारी श्रेणी में चयनित– रक्षा नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग

### मनीष रावत, पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुपालन विभाग

रक्षा नेगी अपनी प्रशासनिक दक्षता, कार्य के प्रति अनुशासन और जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानी जाती हैं। वहीं मनीष रावत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन सेवाओं को मजबूत बनाने, किसानों से सतत संवाद स्थापित करने और तकनीकी परामर्श देने में सराहनीय योगदान दिया है। सम्मान की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलना अत्यंत उत्साहवर्धक है और इससे कार्य के प्रति समर्पण और ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं।

स्व-रोजगार श्रेणी में चयनित–
सूरज कुमार (सीएससी एवं डिजिटल सेवा केंद्र संचालन)
दीपक (बकरी पालन आधारित उद्यम)
शुभम जोशी (फैब्रिकेशन कार्य)

ग्राम कसाणी के सूरज कुमार ने डिजिटल सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक कार्यों को आजीविका का माध्यम बनाया। दीपक, ग्राम काण्डई, ने बकरी पालन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर इसे सफल उद्यम का रूप दिया। वहीं शुभम जोशी, ग्राम कसाणी, ने फैब्रिकेशन क्षेत्र में अपने कौशल के दम पर न केवल स्व-रोजगार खड़ा किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया।

## जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने स्याली सड़क निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। मेरा गाँव-मेरी सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम स्याली की सड़क निर्माण परियोजना की धीमी प्रगति को लेकर मंगलवार को जिला पंचायत सभागार, धारानौला में जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागों के बीच लंबित औपचारिकताओं, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और कार्य में हो रही देरी के कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने निर्माण कार्य के लगातार लंबित रहने पर गंभीर नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि विभागीय लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस मार्ग पर सड़क निर्माण प्रस्तावित है, यदि वहाँ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए, ताकि कार्य बाधित न हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आदेशित किया कि वे

सड़क निर्माण कार्य में तत्काल ठोस प्रगति सुनिश्चित करें और एक समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर निर्माण को शीघ्र गति दें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्याली के ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए परियोजना को अब टॉप प्रायोरिटी के आधार पर पूरा किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया कि सड़क निर्माण में अब किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी।

# हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: सात ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ जब्त

**पथ प्रवाह, हरिद्वार**

राजस्व को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार जनपद में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवैध खनन के विरुद्ध मंगलवार को खनन विभाग ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए लक्सर तहसील क्षेत्र में सात ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ अवैध खनन करते हुए जब्त कीं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों और खनन विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने तथा अवैध खनन पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला खान अधिकारी मौ. काजिम खान ने जानकारी दी कि तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत दूरभाष पर प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर खनन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की टीम के साथ क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सात ट्रैक्टर-ट्रॉलियाँ अवैध रूप से खनन करते हुए पकड़ी गई। ग्रामीणों के सहयोग से सभी वाहनों को पुलिस चौकी भिक्कमपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खनन माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और विभाग किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों, वाहन स्वामियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अवैध खनन पर्यावरण, राजस्व और जनहित–तीनों के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए प्रशासन इसे रोकने हेतु कठोरतम कदम उठा रहा है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि समय पर कार्रवाई संभव हो सके।

## एक नजर

### 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार के 3 दिवसीय स्थापना दिवस मेले का रंगारंग शुभारंभ

पथ प्रवाह, हरिद्वार। 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में आयोजित तीन दिवसीय स्थापना दिवस मेले का शुभारंभ 02 दिसंबर 2025 को मुख्य अतिथि सेनानायक तृप्ति भट्ट द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना कर किया गया। वर्ष 1980 में लखनऊ में स्थापित होने के उपरांत प्रत्येक वर्ष 02 दिसंबर को वाहिनी स्थापना दिवस मनाया जाता है। शुभारंभ अवसर पर उपसेनानायक मनीषा जोशी, सहायक सेनानायक राकेश रावत, जीतो कंबोज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सेनानायक तृप्ति भट्ट ने 40वीं वाहिनी के 45 वर्ष पूरे होने पर उसके अनुभव एवं सेवाभाव को विशेष रूप से रेखांकित किया।

02 से 04 दिसंबर तक आयोजित इस मेले में 'वोकल फॉर लोकल' थीम के तहत पहाड़ी अनाज, फल, मिठाई, अचार, ऊनी वस्त्र, खेल सामग्री, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स और बच्चों के कपड़ों सहित अनेक वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं। सभी सामग्री वाहिनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। मेले का मुख्य आकर्षण लकी ड्रॉ है, जिसमें प्रथम पुरस्कार स्कूटी, द्वितीय पुरस्कार आई-फोन और तृतीय पुरस्कार टीवी सहित लगभग 100 आकर्षक इनाम रखे गए हैं।

मेले में विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं, जबकि पुलिस विभाग द्वारा आपदा एवं बाढ़ रेस्क्यू उपकरण–बोट, स्कूबा शूट, सोनार डिवाइस–की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। महिला कल्याण केंद्र द्वारा तैयार मेजपोश, हैंडमेड ज्वैलरी, पेंटिंग, ऊनी वस्त्र आदि उत्पादों ने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिदिन सायंकालीन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाहिनी ऑर्केस्ट्रा टीम, पुलिस मॉडर्न स्कूल एवं फैमिली लाइन के बच्चों के प्रदर्शन होंगे। 03 दिसंबर को लोक कलाकार श्वेता माहरा विशेष प्रस्तुति देंगी। शुभारंभ दिवस पर श्री लेग रेस, नींबू रेस और रस्साकशी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। 04 दिसंबर को लकी ड्रॉ व सांस्कृतिक संध्या के उपरांत मेले का समापन किया जाएगा।

### ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी के डर से संघर्षविराम पर मजबूर हुआ पाक – वाइस एडमिरल स्वामीनाथन

नई दिल्ली। वाइस एडमिरल के. स्वामीनाथन ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की आक्रामक कार्रवाई के डर के कारण पाकिस्तान ''संघर्षविराम का अनुरोध करने पर मजबूर हुआ।

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने नौसेना दिवस से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही कम समय में 30 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों को अभूतपूर्व तरीके से तैनात किया गया। दुनिया की किसी भी नौसेना के लिए 30 युद्धपोतों का संचालन योग्य होना, जिन्हें चार, पांच या छह दिन के अल्प समय में तैयार करके तैनाती के लिए भेजा जा सके, एक बड़ी बात है। हमारे अग्रिम पंक्ति के जहाज, विमानवाहक पोत विक्रांत के 'कैरियर बैटल ग्रुप के साथ में मकरान तट पर युद्ध के लिए तैयार थे। भारतीय नौसेना की आक्रामक तैनाती और रणनीतिक स्थिति में अप्रैल में एक के बाद एक सफल हथियार परीक्षण शामिल थे। इससे 'पाकिस्तान नौसेना को अपने तट के करीब ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि वास्तव में, भारतीय नौसेना द्वारा आक्रामक कार्रवाई के रुख को पाकिस्तान द्वारा संघर्षविराम का अनुरोध करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जा सकता है। नौसेना हमले के लिए तैयार थी। यदि नौसेना हमला करती, तो तनाव पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता। हम हमला करने के बहुत करीब पहुंच गए थे। हमने कुछ विमान उड़ाये और वायुसेना ने सीमा पार हमला किया। अगर तनाव और बढ़ता, तो हम अंदर घुस जाते। हमारा मानना है कि उन्हें पता चल गया था कि नौसेना आगे बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने संघर्षविराम का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि नौसेना ने उस तनाव को नियंत्रित रखने और उनके लिए खतरा पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। चूंकि हमने उनके लिए खतरा उत्पन्न किया, इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने संघर्षविराम का अनुरोध किया।

# एसपी उत्तरकाशी ने छात्र–छात्राओं को किया सम्मानित, नशा विरोधी संदेश देने पर पुरस्कृत

**पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।**

उत्तराखण्ड राज्य की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह के अवसर पर रामलीला मैदान में आयोजित पुलिस जनजागरूकता कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव पर प्रस्तुत किए गए उत्कृष्ट नुक्कड़ नाटक के लिए एसपी उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने मसीह दिलासा स्कूल के स्टूडेंट्स कलाकारों को सम्मानित किया। इस नुक्कड़ नाटक का निर्देशन शिक्षिका दमयंती ने किया था, जिसकी प्रभावी प्रस्तुति ने आमजन को नशा मुक्ति का सशक्त संदेश दिया। 2 दिसंबर 2025 को पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में आयोजित सम्मान समारोह में एसपी कमलेश उपाध्याय ने छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप लक्ष्य तय कर निरंतर प्रयास करने की है। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की प्रेरणा दी। एसपी कमलेश उपाध्याय ने छात्राओं से उनके सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को भी सुना तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। साथ ही सभी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने, गलत संगत से बचने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की हिदायत दी गई। कार्यक्रम के दौरान डायल 112 की भी विस्तृत जानकारी दी गई और किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर तुरंत कॉल करने के लिए जागरूक किया गया।

# मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने चम्पावत में विकास परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा

**पथ प्रवाह, चम्पावत**

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड आनंद बर्द्धन ने जिला सभागार चम्पावत में जिले की सभी प्रमुख विकास योजनाओं, जनपदीय नवाचारों, मुख्यमंत्री घोषणाओं, केंद्र-राज्य व्यय तथा जनपदीय श्रेष्ठ प्रथाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाएँ समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा परिणामोन्मुखी तरीके से पूर्ण हों और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की जाए।

बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा गोल्ज्यू कॉरिडोर, कृषि महाविद्यालय, पैरामेडिकल कॉलेज, छमनिया स्पोर्ट्स कॉलेज, यूयूएसडीए पेयजल योजना तथा एनएच स्वाला सुधार योजना सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य सचिव ने इन कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए।

समीक्षा से पूर्व मुख्य सचिव ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगे विभागीय स्टॉलों–एनआरएलएम, चाय विकास बोर्ड, डेयरी, कृषि, मत्स्य, रेशम, बागवानी, उद्योग, अक्षय ऊर्जा आदि–का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय नवाचारों और उत्पादों की जानकारी लेते हुए इनको व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा 'आदर्श चम्पावत' का लोगो अनावरण किया।

जिलाधिकारी ने ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी, ज्ञान सेतु पुल, कम्प्यूटर ऑन व्हील और पिरुल ब्रिकेटिंग यूनिट जैसे नवाचारों की जानकारी प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने पंचेश्वर क्षेत्र में एंग्लिंग पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वार्षिक एंगलर्स मीट आयोजित करने तथा चम्पावत-लोहाघाट मास्टर प्लान में भविष्य की आवश्यकताओं–विशेषकर रेलवे विस्तार–को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंडरग्राउंड विद्युतिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए दीर्घकालिक मेंटेनेंस प्लान तैयार करने पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए चम्पावत को एक आदर्श और तेजी से विकसित होने वाले जनपद के रूप में स्थापित करें। बैठक में मंडलायुक्त दीपक रावत, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जनपद की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा के बाद बनाई रणनीति

**पथ प्रवाह, बागेश्वर**

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जनपद की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस और प्रशा?सनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने निर्देशित किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की सुदृढ़ योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जानी है, इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यों को पूरा करें।

बैठक में जनपद में उपलब्ध कुल पुलिस बल, सुरक्षा अधिकारियों, उपकरणों और अन्य संसाधनों का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही वन क्षेत्रों, नदी-तटों तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य भंडारण स्थलों तथा धार्मिक स्थलों जैसे अति महत्वपूर्ण बिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था के मूल्यांकन को भी प्राथमिकता देने को कहा।

साथ ही, किसी भी संभावित आपात परिस्थिति के मद्देनज़र भोजन, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं, दूरसंचार और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जोर दिया कि यह कार्य केवल औपचारिक प्रक्रिया न होकर जनपद की शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ दायित्व है। बैठक में पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर. घोड़के, प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न, मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, उपजिलाधिकारी प्रियंका रानी, सीओ अजय शाह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

# भव्यतम स्वरूप में नजर आयेगा उत्तरायणी मेला 2026: जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे

**पथ प्रवाह, बागेश्वर**

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने उत्तरायणी मेले को दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने मेले को जनता के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई है। मेला भव्यतम स्वरूप में नजर आएगा।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उत्तरायणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर पहली समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने मेले की सज्जा में एकरूपता लाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी दुकानों पर समान फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जाएँ और स्टॉलों को एकसमान ढंग से स्थापित किया जाए, जिससे मेले की सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि हो। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर मेले की भव्यता में कोई कमी न रहने दें।

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने नगरपालिका को सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखने, मुख्य स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट, डस्टबिन और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्थायी शौचालयों में पर्याप्त कार्मिक तैनात करने के निर्देश दिए। जल संस्थान को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए अतिरिक्त स्टैंडपोस्ट लगाने, पुलिस विभाग को कानून-व्यवस्था एवं भीड़ प्रबंधन की प्रभावी तैयारी करने और परिवहन विभाग को यातायात व पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, विद्युत विभाग और उरेडा को मेले के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए। मेले हेतु प्रस्तावित अस्थायी पुलों के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने को कहा गया।

बैठक में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तरायणी मेला बागेश्वर की सांस्कृतिक पहचान है और इसे भव्य बनाने में सभी विभागों तथा स्थानीय जनता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना, मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, एसडीएम प्रियंका रानी, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, विधायक पार्वती दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

## एक नजर

### कोटद्वार में 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' -362 दावों में 4.22 करोड़ रुपये लौटे लाभार्थियों को

पथ प्रवाह, पौड़ी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान के तहत कोटद्वार के मिक्स वेडिंग प्वाइंट, देवी रोड में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य विभिन्न बैंकों में वर्षों से लंबित पड़े वित्तीय दावों का निस्तारण कर जनता की पूंजी को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाना था। जिले में अब तक 362 दावों का निस्तारण करते हुए कुल 4.22 करोड़ रुपये लाभार्थियों को लौटाए जा चुके हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक दीपेश राज ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक की पूंजी अनक्लेम्ड होकर बैंकिंग प्रणाली में अटकी न रहे। बैंकिंग संस्थान इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं ताकि लंबित मामलों का निस्तारण सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित हो सके। दीपेश राज ने कहा कि आज जिन लाभार्थियों को उनका धन वापस मिला है, वह इस जागरूकता और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है। विशेष शिविर में एलआईसी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस समेत अनेक वित्तीय संस्थानों ने काउंटर स्थापित कर उपभोक्ताओं को अनक्लेम्ड खातों, लंबित बीमा दावों और अन्य वित्तीय उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लोगों को आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा दावों के सत्यापन से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं अग्रणी बैंक द्वारा सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों, बैंक प्रतिनिधियों और नागरिकों के प्रति आभार प्रकट किया गया।

इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी मीनाक्षी शुक्ला, एसबीआई के उप महाप्रबंधक विनोद कुमार, भारतीय रिज़र्व बैंक एल.डी.ओ. भरत आनंद, बीमा नियामक प्राधिकरण प्रतिनिधि राजेश झा, सहायक एलडीएम भूपेश नौटियाल, एसबीआई क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज शर्मा सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

# मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पर्यटन विकास परियोजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण

**पथ प्रवाह, चम्पावत**

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड आनंद बर्द्धन ने चम्पावत जनपद के विभिन्न पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बस टर्मिनल से लेकर मायावती आश्रम, कोलीढेक झील और एबट माउंट तक कई प्रमुख स्थलों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को पर्यटन विस्तार, बुनियादी ढांचे के उन्नयन तथा पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण की शुरुआत चम्पावत बस टर्मिनल से हुई, जहाँ निर्माणदायी संस्था सीएनडीएस के अधिशासी अभियंता गिरीश पंत ने प्रस्तावित टर्मिनल की पूरी रूपरेखा मुख्य सचिव को प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने टर्मिनल के भीतर वाहनों की आंतरिक आवाजाही को सुव्यवस्थित करने, यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देने तथा निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके बाद मुख्य सचिव ने मायावती आश्रम का भ्रमण किया, जहाँ स्वामी दिव्य कृपानंद जी ने उन्हें आश्रम परिसर का विस्तृत अवलोकन कराया। मुख्य सचिव ने कहा कि मायावती आश्रम के शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में 'स्पिरिचुअल टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ तैयार की जाएं।

मुख्य सचिव ने कोलीढेक झील का निरीक्षण करते हुए इसे योग, वेलनेस और आध्यात्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य विभाग को महाशीर मछली संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा झील के आसपास के प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखते हुए पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने पर जोर दिया।

एबट माउण्ट के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को अत्यंत समृद्ध बताया। उन्होंने हिमालय की शानदार श्रृंखलाओं का अवलोकन करते हुए कहा कि एबट माउण्ट को उच्चस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने ऐतिहासिक चर्च तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण और सुंदरीकरण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

निरीक्षण के दौरान कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से चम्पावत को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए।

# विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी ने जनसमस्याओं के निस्तारण पर बनाई सुदृढ़ रणनीति

**पथ प्रवाह, पौड़ी**

विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूडी ने जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए सुदृढ़ रणनीति बनाने के लिए जिला प्रशासन, जन प्रतिनिधियों और व्यापारी संगठनों को आमने–सामने बैठा दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जनसमस्याओं को लेकर प्रशासन को संजीदगी से कार्य करना होगा। कोटद्वार शहर में बढ़ती जाम की समस्या, अतिक्रमण, पेयजल-सीवर, पार्किंग और अव्यवस्थित यातायात–का समाधान करना होगा।

भूमि संरक्षण कार्यालय, कोटद्वार में समाधान-केंद्रित बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नागरिक संगठनों ने एक मंच पर आकर शहर को राहत देने के लिए संयुक्त रणनीति पर सहमति जताई।

अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि 'जनसमस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सभी विभाग तालमेल के साथ उत्तरदायी भूमिका निभाएं।' उन्होंने विभागीय ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता व समयबद्धता के साथ किया जाए।

बैठक में नगर निगम महापौर शैलेन्द्र रावत ने जल संयोजन की बाधाएँ, आवारा पशुओं और बंदरों की समस्या का मुद्दा उठाया। अध्यक्षा ने इन चुनौतियों को प्राथमिकता में रखते हुए संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का निर्देश दिया।

व्यापार संघ ने शहर में बढ़ते वाहनों, सीमित पार्किंग, चालानी दबाव और ठेली-फड़ से प्रभावित व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। इस पर अध्यक्षा ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन को 'संतुलित, व्यावहारिक और व्यापार-हितैषी व्यवस्था' तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्यापार मंडल को शामिल किया जाए, ताकि निर्णय पारदर्शी और प्रभावी हों।

स्कूलों के बाहर अक्सर लगने वाले जाम पर उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल बसें परिसर के भीतर ही खड़ी की जाएँ, और ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग एवं पुलिस सतर्क निगरानी रखें।

पार्षदों द्वारा सड़कों की खराब स्थिति, भारी वाहनों से हो रहा नुकसान, नालों की सफाई, एडीबी की धीमी गति, बिजली-संबंधी समस्याएँ और राशन कार्ड अपडेट जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

अध्यक्षा ने समाधान सुझाते हुए कहा कि 'कोई भी विभाग अपने काम से दूसरे विभाग की प्रगति में बाधा न डाले– समन्वित कार्रवाई ही स्थायी समाधान का मार्ग है।'

प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी रजनी जुयाल को निःशुल्क विद्युत संयोजन देने के निर्देश बैठक में ही जारी कर दिए गए। शहर में सूअर पालन, ओवरलोड खनन वाहन, ध्वनि प्रदूषण और कर विभाग से संबंधित मुद्दों की पृथक समीक्षा करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने भरोसा दिलाया कि सभी विभाग दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे और शहर की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त अभियान आगामी पखवाड़े में शुरू कर दिया जाएगा।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, प्रभागीय वनाधिकारी जीवन मोहन दगाड़े, नगर आयुक्त प्यारे लाल शाह, उपजिलाधिकारी शालिनी मौर्य, व्यापार संघ अध्यक्ष पंकज भाटिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

## एक नजर

### भाजपा सरकार की चार साल की उपब्धियां गिनायी

पथ प्रवाह, पिथौरागढ़। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पुष्कर सिंह धामी सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियां प्रेसवार्ता कर गिनायी गई। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत उपस्थित रहे। विकास भगत द्वारा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियां बताई गई। संचालन जिला मंत्री

रघुवीर सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री इंद लुठी, महामंत्री दिवाकर जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष उमेश मेहर, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विप्लव शाह, मंडल अध्यक्ष अशोक भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी कवींद्र शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे।

### चमेठी चंडिका की बनियाथ यात्रा की तैयारियों पर 7 दिसंबर को सिनाउं में महत्वपूर्ण बैठक

पथ प्रवाह, पोखरी/चमोली। नागनाथ पोखरी क्षेत्र के 84 ग्रामों की अधिष्ठात्री भगवती चमेठी चंडिका की बनियाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सिनाउं गांव में आगामी 7 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक चंडिका यात्रा समिति और मंदिर समिति की ओर से समिति अध्यक्ष बीरेंद्र राणा तथा ब्रह्मगुरु ज्योतिषाचार्य कुंवर दीपक सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी। मां चंडिका का मायका और मठापति सिनाउं ग्राम में स्थित है। परंपरा के अनुसार देवी का फर्श (पवित्र प्रतीक) सबसे पहले ब्रह्मगुरु की अगुवाई में सिनाउं लाया जाता है। इस वर्ष भी फर्श आगमन के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय अनुष्ठान और विशेष पूजन आयोजित होंगे। अध्यक्ष बीरेंद्र राणा ने बताया कि इन अनुष्ठानों में सिनाउं गांव के विद्वान खाली ब्राह्मणों और मायके पक्ष के हकूकधारी ब्राह्मणों द्वारा देवी फर्श की प्राण-प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न की जाएगी।

# अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त डीएम, बोले जनप्रतिनिधियों के फोन करें रिसीव

## जनता की समस्याओं का त्वरित करें समाधान, डीएम ने अधिकारियों को दिये निर्देश

**पथ प्रवाह, पिथौरागढ़।**

जिला पंचायत सभागार पिथौरागढ़ में अध्यक्ष जिला पंचायत जितेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सामान्य/बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न विकास कार्यों एवं क्षेत्रीय समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत जनता की आवाज़ का सबसे मजबूत मंच है, इसलिए विभागीय अधिकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान में तत्परता रखें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा विद्युत कटौती, पेयजल आपूर्ति में बाधा, लिफ्ट पेयजल योजनाओं में तकनीकी दिक्कतें, सड़क निर्माण में विलंब, चिकित्सा सेवाओं में कमी तथा विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन न रिसीव करने पर भी कड़ा ऐतराज दर्ज किया गया।

**समस्याओं को जांच के बाद करें दूर**

जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि– जनप्रतिनिधियों के कॉल व संदेशों का तुरंत उत्तर सुनिश्चित करें। विद्युत एवं पेयजल समस्याओं को फील्ड निरीक्षण कर शीघ्र दूर किया जाए। प्रत्येक विभाग साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे, देरी या लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी। विद्युत विभाग, जल निगम, जल संस्थान सहित सभी संबद्ध विभागों ने अपनी कार्ययोजनाएं सदन के समक्ष प्रस्तुत की और समस्याओं के त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

**लापरवाही बर्दाश्त नहीं**

अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद एवं उपाध्यक्ष दीपिका चुफाल ने स्पष्ट कहा कि – 'जनहित सर्वोपरि है – किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।' जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि सदन में उठाई गई प्रत्येक जनसमस्या को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा तथा सभी विभाग पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ कार्य करेंगे। बैठक में जिला पंचायत सदस्य, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# जनता के दिलों को छूने लगे जिलाधिकारी, समस्याओं के निस्तारण में तत्परता जारी

**पथ प्रवाह, अल्मोड़ा**

तहसील लमगड़ा में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए विभागों को त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाई और लापरवाह अधिकारियों को क्लास लगाई। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, राशन और कूड़ा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने को कहा। पीएमजीएसवाई सड़कों से संबंधित शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जांच कर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। यदि आवश्यक कटौती हो तो उसकी पूर्व सूचना जनता तक अवश्य पहुंचे।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने पेयजल समस्या पर जल संस्थान को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें और किसी भी क्षेत्र में पानी की किल्लत न होने पाए। राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के लिए एसडीएम स्तर पर तहसील स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान किया जा सके।

कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बीडीओ लमगड़ा की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाने को कहा, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी रणनीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तहसील दिवस में कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को निर्धारित अवधि में समाधान हेतु संबंधित विभागों को सौंपा गया।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com